



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4459]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2018/कार्तिक 21, 1940

No. 4459]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2018/KARTIKA 21, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

का.आ.5674(अ).—केन्द्रीय सरकार, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना समीचीन है, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

***चौथी अनुसूची**

[धारा 11 की उपधारा (14) देखें]

क्रम सं.	विवादित राशि	मॉडल फीस
(1)	(2)	(3)
1.	5,00,000 रुपए तक	45,000 रुपए
2.	5,00,000 रुपए से अधिक और 20,00,000 रुपए तक	45,000 रुपए + 5,00,000 रुपए से अधिक की दावा रकम का 3.5 प्रतिशत।
3.	20,00,000 रुपए से अधिक और 1,00,00,000 रुपए तक	97,500 रुपए + 20,00,000 रुपए से अधिक की दावा रकम का 3 प्रतिशत।

4.	1,00,00,000 रुपए से अधिक और 10,00,00,000 रुपए तक	3,37,500 रुपए + 1,00,00,000 रुपए से अधिक की दावा रकम का 1 प्रतिशत।
5.	10,00,00,000 रुपए से अधिक और 20,00,00,000 रुपए तक	12,37,500 रुपए + 10,00,00,000 रुपए से अधिक की दावा रकम का 0.75 प्रतिशत।
6.	20,00,00,000 रुपए से अधिक	19,87,500 रुपए + 20,00,00,000 रुपए से अधिक की दावा रकम का 0.5 प्रतिशत, 30,00,000 रुपए की अधिकतम सीमा सहित।

टिप्पण : माध्यस्थम् अधिकरण के एकमात्र माध्यस्थ होने की दशा में, वह ऊपर दी गई सारणी के अनुसार संदेय फीस की पञ्चीस प्रतिशत अतिरिक्त रकम का हकदार होगा।”।

2. यह अधिसूचना 23 अक्तूबर, 2015 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[फा.सं. 10 (1)/2017-वि. III]

के. बिस्वाल, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की चौथी अनुसूची में “विवादित राशि” शीर्षक के अधीन ‘10,00,00,000 रुपए से अधिक और 20,00,00,000 रुपए तक’ प्रविष्टि के सामने ‘12,37,500 रुपए+ 10,00,00,000 रुपए से अधिक दावा रकम का 0.75 प्रतिशत’ के स्थान पर मॉडल फीस को असावधानीवश 12,37,500 रुपए+ 1,00,00,000 रुपए से अधिक रकम का 0.75 प्रतिशत वर्णित कर दिया गया है। अतः, उक्त अनुसूची का माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 3) के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्वोक्त का सुधार करने के लिए संशोधन किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि माध्यस्थम् का कोई पक्षकार इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2018

S.O. 5674(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996), the Central Government being satisfied that it is expedient to do so, hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Arbitration and Conciliation Act, 1996, for the Fourth Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“THE FOURTH SCHEDULE

[See sub-section (14) of section 11]

Sl.No.	Sum in dispute	Model fee
(1)	(2)	(3)
1.	Up to Rs.5,00,000	Rs.45,000
2.	Above Rs.5,00,000 and up to Rs. 20,00,000	Rs. 45,000 plus 3.5 per cent. of the claim amount over and above Rs.5,00,000.
3.	Above Rs.20,00,000 and up to Rs. 1,00,00,000	Rs.97,500 plus 3 per cent. of the claim amount over and above Rs.20,00,000.
4.	Above Rs.1,00,00,000 and up to Rs. 10,00,00,000	Rs.3,37,500 plus 1 per cent. of the claim amount over and above Rs.1,00,00,000.

5.	Above Rs.10,00,00,000 and up to Rs. 20,00,00,000	Rs.12,37,500 plus 0.75 per cent. of the claim amount over and above Rs.10,00,00,000.
6.	Above Rs. 20,00,00,000	Rs.19,87,500 plus 0.5 per cent. of the claim amount over and above Rs.20,00,00,000 with a ceiling of Rs.30,00,000.

Note: In the event the arbitral tribunal is a sole arbitrator, he shall be entitled to an additional amount of twenty-five per cent. on the fee payable as per the above.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 23rd day of October, 2015.

[F. No.10(1)/2017-Leg.III]

K. BISWAL, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum

In the Fourth Schedule to the Arbitration and Conciliation Act, 1996, under the heading ‘Sum in dispute’, against the entry ‘Above Rs.10,00,00,000 and up to Rs.20,00,00,000’, the model fee is inadvertently mentioned as ‘Rs.12,37,500 plus 0.75 per cent. of the claim amount over and above Rs.1,00,00,000/’ instead of ‘Rs.12,37,500 plus 0.75 per cent. of the claim amount over and above Rs.10,00,00,000/’. Hence, the said Schedule is amended to rectify the above with effect from the date the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015 (3 of 2016) came into force. It is certified that no party to arbitration will be prejudicially affected by the retrospective effect being given to this amendment.